(c) The total acreage under the crop (1967-68) is estimated at about 9 lakhs hectares and the total production at 5319 million nuts (approximately 2·7 lakhs tonnes of copra). Under the Fourth Plan, it is envisaged to achieve an additional production of 1000 million nuts. This target is sought to be achieved by the implementation of coconut development schemes including the Centrally Sponsored Schemes. Besides schemes that will yield immediate results, some other schemes which are of potential importance in future will also be undertaken during the Fourth Plan.

Both short term and long term coconut development programmes are in progress in various states. The short term measures include setting up of demonstration plots, distribution of fertilizers, introduction of package programme, promotion of irrigation facilities and control of pests of and diseases. Long term measures include expansion of area under the crop and production and distribution of quality planting material.

चौथी योजना में राज्य क्षेत्र के आकार के बारे में निर्णय

795. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में राज्य क्षेत्र के आकार के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी कितनी धन राशि की मांग की थी तथा प्रत्येक को वस्तुत: कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अंतिम निर्णय संभवत: कबतक किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद्, जिसकी बैठक आगामी वर्ष के आरम्भ में होने की संभावना है, द्वारा विचार करने के बाद, राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा ।

Draft Plan for Orissa

796. SHRI RABI RAY:

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Orissa had discussions with the Planning Commission about the size of their State Plan;

of(b) if so, whether he demanded that the Centre should come to the aid of the Government of Orissa in view of its low per capita income; and

(c) the assurance given to the Chief Minister on that score ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The State Chief Minister was assured that the question would be considered while finalising the State's Fourth Plan.

Boundary Demarcation Between East Pakistan and West Bengal

*797. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pakistan authorities did not agree to border demarcation at a Dacca meeting recently;

(b) if so, how much boundary has been demarcated between East Pakistan and West Bengal and how much boundary is yet to be demarcated;

(c) when agreement on boundary demarcation was reached and when the work on demarcation started; and

(d) the disputes that have arisen on demacration, which of them have been settled and which remain to be settled ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) and(b). Out of 1349 Linear miles of boundary between West Bengal and East Pakistan only 95 linear miles are yet to be demarcated. The Pakistan authorities have refused to cooperate in demarcating certain sectors of this boundary unless demarcation on the Berubari Sector, consisting of 26 linear miles, is completed.

(c) The Radcliffe Award of 12th August 1947 was the basis of the boundary demarcation between the West Bengal and East Pakistan and demarcation began after the Inter-Dominion Conference at New Delhi in December 1948.

(d) The major differences between the two countries were regarding:

(1) the boundary between Murshidabad (India) and Rajshahi (East Pakistan),

(2) the boundary in Berubari,

(3) the boundary between 24 Parganas (India), and Jessore-Khulna (East Pakistan),

(4) the boundary along Hili,

(5) the Chhit lands of old Cooch Behar State and its Enclaves in Pakistan and Pakistani Enclaves in India,

(6) the Mahananda—Borung Karatoa region.

Except for a minor difference over the interpretation of the Nehru-Noon Agreement regarding 24-Parganas and Jessore-Khulna border, there is no dispute pending between the two countries.

नेपाल द्वारा व्यापार करार का पालन

*798. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारत और नेपाल के बीच हुए व्यापार करार की सभी शर्तों और निबंधनों का नेपाल ने पालन नहीं किया है;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान इस करार का अनुचित लाभ उठा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ग). नेपाल की सरकार के साथ हमारा ऐसा कोई व्यापार करार नहीं है। माननीय सदस्य का निर्देश प्रत्यक्षत: व्यापार तथा पारगमन के सम्बन्ध में भारत-नेपाल संधि (1960) की ओर है।

2. समय-समय पर प्राप्त हुई शिकायतें मुख्यत: नेपाल द्वारा भारत को संश्लिष्ट वस्त्रों तथा अविकारी इस्पात के सामान के अत्यधिक निर्यातों, भारत में नेपाल से अन्य देशों के माल का प्रवाह और नेपाल द्वारा अन्य देशों को भारतीय माल के भेजने से सम्बन्धित हैं।

3. नेपाल सरकार संश्लिष्ट वस्त्र तथा अविकारी इस्पात के माल के अपने निर्यातों को 1967-68 के स्तर पर सीमित करने के लिये सहमत हो गई है। अन्य देशों में बने माल का जहां तक सम्बन्ध है, नेपाल से भारत में उनके **आयात पर सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना** द्वारा रोक लगा दी गई है। ऐसे माल का भारत में चोरी-छिपे आना रोकने के लिये और अन्य देशों को भेजने के लिये भारतीय माल का नेपाल में चोरी-छिपे जाना रोकने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) सीमा पर अतिरिक्त सीमा शुल्क कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(2) सीमा पर कार्य करने वाले केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य प्रवर्तन अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करना ;

(3) केन्द्र तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई है, जो समय समय पर समीक्षा करके भारत-नेपाल सीमा के आर-